ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

गठबंधन की राजनीति और यू.पी.ए–2 का पतन

Coalition Politics and The Fall of UPA-2

अरविंद वर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग,
एम. एस. जे. राजकीय महविद्यालय, भरतपुर
राजस्थान, भारत

आशा परमार
सह आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग,
एम. एस. जे. राजकीय महविद्यालय, भरतपुर
राजस्थान, भारत

सारांश

केंद्रीय स्तर पर गठबंधन भारतीय राजनीति का न्यू नार्मल बन चुका है एक बड़े केंद्रीय दल के इर्द गिर्द कमोबेश विचारधारात्मक प्रतिबद्धताओं को दरकिनार करके छोटे छोटे दलों का सम्मिलिन सत्ता सुख की चाह में हो जाता है एन.डी.ए के शासन के पश्चात अप्रत्याशित तौर पर सन 2004 में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व वाले यू.पी.ए –1 का शासन स्थापित हुआ, यू.पी.ए शासन दो अतियों का अभूतपूर्व संगम था एक तरफ एतिहासिक लोककल्याणकारी योजनाओं को इस काल में अमलीजामा पहनाया गया वहीँ दूसरी तरफ घोटालों के गंभीर आरोप भी इस सरकार पर लगे । यू.पी.ए–2 के शासन के दौरान विभिन्न ओद्योगिक घरानों और सरकार के मध्य सम्बन्ध नए निम्नतम स्तर तक पहुँच गए, टाटा,बिरला अम्बानी जैसे बड़े ओद्योगिक नाम भी किसी न किसी घोटाले में आने लगे, देश की ओद्योगिक विकास की रफ्तार एक दम थम गई और परिणामतः यू.पी.ए सरकार भी अंतत एतिहासिक हार की ओर उन्मुख हो गई ।

At the central level, coalition has become the new normal of Indian politics, bypassing ideological commitments more or less around a large central party, the power of smaller parties to join in the desire for happiness is unexpectedly after the rule of NDA In 2004, the Congress-led UPA-1 rule was established, the UPA rule was an unprecedented confluence of two extremes, on one side, historical public welfare schemes were implemented during this period, while on the other side, serious scams Accusations were also leveled against this government. During the UPA-2 regime, relations between various industrial houses and the government reached a new low, big industrial names like Tata, Birla Ambani also started getting into some scam, the country's industrial development speed was a Stagnated and as a result, the UPA government too was finally oriented towards historical defeat.

मुख्य शब्द :गठबंधन की राजनीति, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायन्स), मनमोहन–सोनिया–राहुल ट्रोइका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना (NRHM), कृषि ऋण माफी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNAREGA), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सब प्राइम संकट और लेहमेन संकट, जीडीपी विकास दर, 2 जी रिपोर्ट, कोलगेट, सीबीआई, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट–पोलिटिशियन, कॉर्पोरेट लॉबिंग।

Coalition politics, United Progressive Alliance (United Progressive Alliance), Manmohan-Sonia-Rahul Troika, National Rural Health Mission Scheme (NRHM), Agricultural Debt Waiver Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme ((MGNAREGA), Comptroller and Auditor General Examiner, Sub Prime Crisis and Lehman Crisis, GDP Growth Rate, 2G Report, Colgate, CBI, Enforcement Directorate, Corporate Marketing, Corporate-Politician, Corporate Lobbying

प्रस्तावना

गठबंधन राजनीति बहुदलीय सरकार की एक विशेषता है जहाँ कई अल्पसंख्यक दल सरकार चलाने के लिए हाथ मिलाते हैं। गठबंधन तब बनता है, जब कई विरोधी समूह बहुमत बनाने के लिए अपने व्यापक अंतरों को छोड़ कर एक साझा मंच पर हाथ मिलाने के लिए सहमत होते हैं। गठबंधन सरकार संसदीय लोकतंत्र में राजनीति का एक उप– उत्पाद है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था के अस्तित्व के कारण विकास है। गठबंधन सरकार

तब गठित होती है जब कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। इस प्रकार, एक बहुमत पार्टी प्रणाली ऐसी स्थिति कई अल्पसंख्यक दलों के साथ आने और गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम बनाती है। भारतीय राजनीति में, गठबंधन विभिन्न राजनीतिक समूहों की अवसरवादी शक्ति से प्रेरित मानसिकता को दर्शाता है। भारत अनेकों विविधताओं और बहुलताओं का देश होने के बावजूद एकजुट है, यह निरंकुश और क्षेत्रीय विचारों से प्रेरित है।[1] इसलिए गठबंधन केवल सत्ता पर कब्जा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के एक साथ आने का प्रयास ही नहीं है, यह जमीनी स्तर पर सामाजिक हितों के विखंडन का भी प्रतिबिंब है। भारत में राजनीति हमेशा अलग–अलग राजनीतिक दलों के भीतर निहित गठजोड़ के लिए बाध्य करती रही है।[2]

मनमोहन–सोनिया–राहुल ट्रोइका ने एक व्यक्ति नेतृत्व को चुनोती दी थी, जिसने पांच साल तक काम किया और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 200 सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम हुए । कांग्रेस का यह उल्लेखनीय प्रदर्शन मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आपसी नेतृत्व और समझ के कारण संभव हो पाया था। कांग्रेस द्वारा 2009 तक किए गए कामों का लाभ और प्रशंसा यूपीए को नहीं मिल पाई क्योंकि यूपीए सरकार 2 जी और कोयला घोटाले, बेरोजगारी दर में वृद्धि, मूल्य वृद्धि और देश के पिछले दो वर्षों में देश को झकझोरने वाले कई घोटालों से अवरुद्ध हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में एक साथ दो धाराएं चल रही थीं। पहली धारा कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत सत्ता–विरोधी लहर थी जिसने इसे सीटों की संख्या 44 तक पहुंचा दिया जो अब तक के इतिहास में सबसे कम है और इसका वोट शेयर भी 20% से नीचे गिर गया। दूसरी लहर भाजपा के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी जिसने भगवा पार्टी को दिल्ली में सत्ता में वापस लाने में मदद की और भगवा पार्टी के लिए एक आसान बहुमत के साथ सत्ता की राजनीति के राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम में भाजपा के वर्चस्व के उद्घाटन का संकेत दिया।

अध्ययन के उद्देश्य

यह लेख उन कारणों पर प्रकाश डालता है जिनकी वजह से एतिहासिक रूप से बिग टिकट रिफार्म और जनकल्याणकारी योजनायें लागू करने के बावजूद यू. पी.ए सरकार को जाना पड़ा और कांग्रेस को एतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। इस काल में शायद ही कोई बड़ा ओद्योगिक घराना हो जो किसी न किसी विवाद में न फंसा हो अथवा किसी न किसी घोटाले में उसका नाम न आया हो, इसका परिणाम भी विश्लेषण योग्य है समीचीन है। यू.पी.ए के द्वितीय कार्यकाल में कैग की भूमिका भी ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसके सकारत्मक और नकारात्मक बिंदु विश्लेषण योग्य हैं।

यू पी ए सरकार सन 2004 से सन 2014 में अपने दो कार्यकालों की लंबी अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना (NRHM), कृषि ऋण माफी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNAREGA) जैसी भारतीय लोगों की भलाई के लिए कई राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत की।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए) सरकार के दोनों कार्यकाल विविधताओं से भरे रहे, इन कार्यकालो में न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा की ऐतिहासिक योजनाओं की सफलता और ओचित्य पर प्रश्नचिंह लगाये गए अपितु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक सहित अरुण जेटली ने भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार को ऐतिहासिक रूप से अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार घोषित कर दिया।[2] जी और कोयला खदानों के आवंटन के मुद्दे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को सूचनाओं की बाढ़ से भर दिया, इस रिपोर्ट ने सरकार की आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाये और सरकारी खजाने को इस अविवेक पूर्ण आवंटन से क्रमशः 1.76 लाख करोड़ और 1. 86 लाख करोड़ के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया ।

यह वह दौर भी है जिसमें विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था अमेरिका के सब प्राइम संकट और लेहमेन संकट ने विश्व अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी, विकासशील देशों की मुद्रा के मूल्य में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, कच्चे तेल के भाव 150 डॉलर प्रति बेरल तक पहुँच गए, परिणाम स्वरुप भारत में मुद्रा स्फीति की दर विशेष कर खाद्य महंगाई दर ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच गई ।

यह दौंर गठबंधन की तमाम कमजोरियों से भरा हुआ था। ममता बनर्जी अधिकाँश समय कोई न कोई सोदेबाजी करती दिखाई दी, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2 जी रिपोर्ट पर अधिकाँश समय केंद्र सरकार पर दबाव बनाती दिखाई दीं, समाजवादी पार्टी यद्यपि बाहर से समर्थन दे रही थी परन्तु सरकार के अंतिम एक वर्ष में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मोल तोल की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया ।

इस दौर में आतंरिक राजनीतिक परिदृश्य भी अनेक उठा पटक से भरा रहा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएमओ के दबाव और विशेषकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी के दबाव में निर्णय लेने के आरोप लगते रहे । मायावती, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी सौदेबाजी का कलात्मक प्रदर्शन इस दौर में किया, मुलायम सिंह यादव ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अंतिम दो वर्ष के कार्यकाल में अनेक बार समर्थन वापस लेने की धमकी दी, ममता बनर्जी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह यादव की सौदेबाजी की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई ।

71 इस दौर मे सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अति सक्रियता दिखाई। अनिल अम्बानी, मुकेश अम्बानी, टाटा समूह, बिरला समूह, जिंदल समूह सहित देश के अनेक बड़े ओद्योगिक घरानों पर न सिर्फ मुकदमे दायर हुए अपितु अनेक बड़े उद्योगपति जेल भी गए। इस स्थिति ने तमाम ओद्योगिक गतिविधिओं को न सिर्फ धीमा कर दिया अपितु सम्पूर्ण व्यापार जगत को असमंजसता से भर दिया. इस सबका परिणाम यह हुआ

की देश में आर्थिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ने लगीं और देश की जीडीपी विकास दर कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 5% से भी नीचे चली गयी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के द्वितीय कार्यकाल के दौरान विभिन्न ओद्योगिक घरानों और केंद्र सरकार के मध्य सम्बन्ध अपने निम्न स्तर तक पहुँच गए, 2 जी और कोल् मामले पर कॉर्पोरेट मार्केटिंग और कॉर्पोरेट–पोलिटिशियन सम्बन्ध के अनेक मामले सामने आये, कॉर्पोरेट लोबिंग स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उभर कर सामने आई जिससे भारत के सबसे प्रतिष्ठित ओद्योगिक घराने टाटा भी बच न सके। इस राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से यह देखना एक बड़ा ही रोचक पहलु है की राजनीतिक नीति निर्माण में ओद्योगिक घरानों की क्या भूमिका होती है और किस तरह ये न सिर्फ नीति निर्माण को अपने हितों के अनुरूप बनवाने का दबाव डालते हैं अपितु यदि ये नीतियाँ इनके अनुकूल न बने तो उसके क्या परिणाम राजनीतिक नेतृत्व को भुगतने पड़ते हैं ?

सूचना क्रांति के दौर में मीडिया की भूमिका राजनीतिक जनमत बनाने में बिना किसी संशय के सबसे महत्वपूर्ण है । खबरें जिस तेजी से प्रसारित और प्रचारित की जाती हैं उसके मध्य जनता का तारतम्य भी राजनितिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण बिंदु है ।

भारत के भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनोद राय ने अपनी पुस्तक 'नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट' में यह जोर देकर लिखा की कैग का काम सिर्फ कंप्यूटर की तरह दिए गए डाटा को विश्लेषित करना ही नहीं है अपितु कैग का काम सरकार की नीतियों के ओचित्य का भी परीक्षण करना है न सिर्फ 2 जी बल्कि कोल् आवंटन की बारीकियों को समझने में यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है ।[3]

भूतपूर्व सेक्रेटरी कोल् पी.सी. पारख ने अपनी पुस्तक 'क्रूसेडर और कांस्पिराटर' में निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पर आतंरिक मंत्रालयिक पत्र व्यवहार के माध्यम से कोल् आवंटन में जानबूझकर चुप रहने के आरोप लगाये हैं । पी.सी. पारख ने कैग के समर्थन में भी अनेक दलील इस पुस्तक में दी हैं ।[4]

भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुख्य मीडिया सलाहकार और पीएमओ के प्रवक्ता संजय बारू ने अपनी पुस्तक 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में स्पष्ट रूप से लिखा है की मनमोहन सिंह कभी भी सोनिया गांधी की छाया से बाहर नहीं निकल पाए । हर निर्णय में सोनिया गांधी का दखल रहता था।[5]

प्रमुख मीडिया जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने अपनी पुस्तक '2014 द इलेक्शन देट चेंज्ड इंडिया' में नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के उदय और कांग्रेस सरकार के दौरान हुए विभिन्न घटना क्रम पर बारीकी से ध्यान दिया है राजदीप सरदेसाई ने नए तरह के प्रचार को भी अपने अध्ययन का बिंदु बनाया है की किस तरह मल्टीमीडिया के उपयोग से लहर को सुनामी में बदला जा सकता है ।[6]

मैतरेश घाटक,परीक्षित घोष और अशोक कोटवाल ने इकनोमिक एंड पॉलिटिकल साइंस वीकली के अपने आर्टिकल 'ग्रोथ इन द टाइम ऑफ यू.पी.ए., मिथ एंड रियलिटी' 2014 में लिखा है की यू.पी.ए. सरकार के बारे में बने अभिमत और वास्तविकता में गंभीर अंतर है यू.पी.ए. सरकार के दस वर्ष के शाशन काल और एन.डी.ए. सरकार के पांच वर्ष के शासन काल की यदि तुलना की जाए तो यू.पी.ए. सरकार उपलब्धियों के मामले में कहीं आगे है ।[7]

द सन्डे ट्रिब्यून ने अपने 9 मार्च 2014 के लेख 'हेड ए प्लाट,लॉस्ट इट टू स्कैम्स' में लिखा है कि यू.पी.ए. ने गरीबी हटाने के कार्यक्रम से लेकर लैंड बिल तक सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत से काम किये, परन्तु नियमित अंतराल पर एक के बाद एक उभरते घोटालों का यू.पी.ए. के पास कोई उत्तर नहीं था।[8]

लॉरेंस सेज और गुरहरपाल सिंह ने अपनी पुस्तक 'न्यू डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया' (द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायन्स) 2014 में गठबंधन सरकार की बाध्यताओं पर गहराई से शोध किया है साथ ही यू.पी.ए. सरकार अपने द्वितीय कार्यकाल में किन सकारात्मक उपलब्धियों के बल पर 2009 का चुनाव जीती उनका आलोचनात्मक परीक्षण किया है ।[9]

मई 2014 के लोकसभा चुनाव और कांग्रेस सहित यू .पी. ए. की एतिहासिक और शर्मसार कर देने वाली हार ने जनता के मन में यह बिठा दिया कि यू.पी.ए. की सरकार ने कोई काम गत वर्षों में नहीं किया, परिणाम चाहे जो रहे हों पर इससे परिणाम यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि हमेशा यह जरूरी नहीं है की आपकी उपलब्धियों और प्रयासों के अनुरूप ही परिणाम आयें, वास्तव में यू.पी.ए सरकार के 10 वर्ष के शासन काल में विश्व आर्थिक परिद्रश्य के नकारात्मक माहोल के बावजूद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक संकेतकों के स्तर पर अभूतपूर्व योगदान दिया था।

निष्कर्ष

तत्कालीन कैग विनोद रॉय की गड़ना पद्धति, और विभिन्न सरकारी नीतियों पर प्रश्नचिंह लगाने की उनकी अनोखी कला ने एक नया आभासी आभामंडल बनाया जिसे ओद्योगिक घरानों के द्वारा पोषित विभिन्न मीडिया चैनलस ने खूब हवा दी, यह आभामंडल तो आभासी था परन्तु इसके परिणाम धरातल पर कांग्रेस के एतिहासिक पतन के रूप में सामने आये, यदि यू.पी.ए सरकार की अंतिम दो तिमाही की न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर को भी जोड़ दें तब भी यू.पी.ए सरकार के अंतिम दस वर्ष के शासन काल में ओसत वृद्धि दर 8.1: रही जो सारी हकीकत स्वयं ही बयान कर देती है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *लिविंगस्टन, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, ऑक्सफोर्ड, क्लेयरडॉन, 1956, पेज 2।*
2. *बिद्युत चक्रवर्ती, इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी सिसिली इंडिपेंडेंस: इवेंट्स प्रोसेसेस एंड आइडियोलॉजी, न्यू वर्क, रूटलेज, 2008, पृष्ठ.153।*
3. *विनोद राय, 'नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट' रूपा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2014*
4. *पी.सी. पारख, 'क्रूसेडर और कांस्पिराटर' मानस पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2014*

5. संजय बारू, 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पेंगुइन पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2014
6. राजदीप सरदेसाई, '2014 द इलेक्शन देट चेंज्ड इंडिया' वाइकिंग पेंगुइन नई दिल्ली, 2015
7. मैतरेश घाटक,परीक्षित घोष और अशोक कोटवाल, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल साइंस वीकली ' ग्रोथ इन द टाइम ऑफ यू.पी.ए., मिथ एंड रियलिटी' 2014
8. द सन्डे ट्रिब्यून, 9 मार्च 2014 'हेड ए प्लाट,लॉस्ट इट टू स्कैम्स' 2014
9. लॉरेंस सेज और गुरहरपाल सिंह, 'न्यू डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया' (द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायन्स) रूटलेज प्रेस लन्दन, 2017